संपादकीय जागरण

मंगलवार, 21 अगस्त, 2018 : श्रावण शुक्ल 11 वि. 2075

सफलता कोई पड़ाव नहीं बल्कि अनवरत चलने वाली यात्रा है

पाकिस्तान को संदेश

भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को चिट्ठी भेजकर बधाई देने और उसमें दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों की अपेक्षा व्यक्त करने में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे लेकर सवाल खड़े किए जाएं। समझना कठिन है कि कुछ लोग इस चिट्ठी का मजमून जाने-समझे बिना आलोचना करने के लिए आगे क्यों आ गए? इतना उतावलापन ठीक नहीं। विदेश नीति के मामले में तो यह और भी आवश्यक है कि सारी बात जान-समझकर ही प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए। यह अच्छा हुआ कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय प्रधानमंत्री ने उनके प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी में बातचीत की कोई पेशकश नहीं की है, लेकिन यह भी उसे ही बताना चाहिए कि जब ऐसी कोई पेशकश की ही नहीं गई थी तो फिर विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने कथन से यह आभास क्यों कराया कि भारत नए सिरे से वार्ता के लिए तैयार है? इससे उत्साहित नहीं हुआ जा सकता कि पाकिस्तान की ओर से यह भी कहा गया कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी यह कहना चाह रहे थे कि भारतीय प्रधानमंत्री ने रचनात्मक शुरुआत की बात कही है और दोनों देशों के बीच सारी समस्याओं का समाधान सतत बातचीत ही है। इसमें दोराय नहीं कि दोनों देशों के बीच सार्थक संबंध तभी संभव हैं जब उनमें किसी न किसी स्तर पर बातचीत होगी, लेकिन मौजूदा हालात में भारत की ओर से पाकिस्तान के समक्ष यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि बातचीत के लिए उपयुक्त आधार तैयार करने का काम उसका ही है और यह उसे करना ही होगा।

निःसंदेह इमरान खान परंपरागत नेता नहीं हैं और उन्होंने चुनावी जीत के बाद अपने भाषण में कश्मीर समस्या का जिक्र किए बिना भारत से संबंध सुधारने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन केवल इतने से बात बनने वाली नहीं है। उन्हें भारत से बातचीत के पहले यह भरोसा दिलाना होगा कि पाकिस्तान वार्ता के साथ ही आतंकवाद जारी रखने की अपनी नीति से बाज आ चुका है। पाकिस्तान की कमान संभालने वाले क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान भारत संबंधी नीति में कुछ फेरबदल करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी सेना उन्हें ऐसा करने की इजाजत देगी, जो भारत के लिए खतरा बने आतंकी संगठनों को अपना सहयोगी मानती है? इसका कोई मतलब नहीं कि पाकिस्तान से केवल इसलिए नए सिरे से बातचीत की जाए कि वहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है। यह काम वहां कई बार हो चुका है और अभी तक का अनुभव यही बताता है कि भारत को धोखा देने की उसकी उस नीति में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है जिसके सूत्र पाकिस्तानी सेना और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी आइएसआइ के हाथों में हैं। भारत यह नहीं भूल सकता और न ही उसे भूलना चाहिए कि जब-जब पाकिस्तान के कपट भरे इरादों की अनदेखी करके उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया उसने पीठ पर वार ही किया है। पाकिस्तान से बातचीत में हर्ज नहीं, लेकिन आखिर इसकी गारंटी कौन लेगा कि पाकिस्तानी सेना अपने आतंकियों से गुरदासपुर, पठानकोट, उड़ी, नगरोटा जैसे आतंकी हमले नहीं कराएगी?

अन्नदाता की फिक्र

यह सुखद संकेत है कि किसान, धान और गेहूं के साथ अब ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाज की खेती को फिर अपना रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले 31 हजार हेक्टेयर अधिक रकबे में मोटे अनाजों की बोवाई से स्पष्ट है कि सिंचाई संकट और भारी लागत ने किसानों को उन अनाजों की ओर लौटने पर बाध्य किया है जो कम लागत और बिना झंझट अच्छी उपज देते हैं। वैसे मोटे अनाजों की खेती के प्रति किसानों के आकर्षण की एक बड़ी वजह केंद्र सरकार द्वारा इन जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी भी है। केंद्र सरकार के इस कदम के बाद खेती के अलाभकारी व्यवसाय होने की धारणा किसी हद तक कमजोर पड़ी है। यह धारणा तोड़ने में मोटे अनाज की फसलों की अहम भूमिका है जो आसानी से अच्छी उपज देते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प जताया है।

आजादी के बाद यह पहला अवसर है जब किसी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बाकायदा रोडमैप तैयार किया है

आजादी के बाद यह पहला अवसर है जब किसी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बाकायदा रोडमैप तैयार किया है। सरकार ने इसकी रणनीति में जो योजनाएं शामिल की हैं, वे उम्मीद जगाती हैं कि जल्द ही किसानों के अच्छे दिन आएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। सबसे बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश की सरकार और किसानों की जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार के लक्ष्य संधान में अपनी भूमिका पूरी गंभीरता के साथ निर्धारित करें। प्रदेश के किसान साबित कर चुके हैं कि उन्हें सरकार का सहयोग मिले तो वे क्रांतिकारी नतीजे दे सकते हैं।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या केरल में आई आपदा प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा है?

आज का सवाल

क्या विपक्ष का यह आरोप सही है कि केंद्र सरकार केरल की अनदेखी कर रही है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

परिपक्वता से परे हटती राजनीति

जगमोहन सिंह राजपूत

पक्ष-विपक्ष की राजनीति में इस समय गंभीरता की जो भारी कमी दिखाई दे रही है वह किसी न किसी रूप में हर स्तर पर लोगों का ध्यान खींच रही है

इन दिनों समाचार माध्यमों और खासकर टीवी चैनलों में किसी विषय पर अपनी बात रख रहे पक्ष और विपक्ष के नेताओं के रवैये से यही स्पष्ट होता है कि वर्तमान राजनीति में चुनाव परिणामों से महत्वपूर्ण कुछ और है ही नहीं। अधिकांश चैनलों पर बहस विमर्श के नाम पर स्तरहीनता, अज्ञानता, राजनीतिक नासमझी और हर हाल में दलगत प्रतिबद्धता के भाव ही दिखाई पड़ते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्थितियों की जानकारी और भारत के संबंध में उनकी महत्ता जैसे विषय आज के विमर्श में मुश्किल से ही कोई जगह बना पाते हैं। आगामी चुनावों और उनके परिणामों पर चर्चाएं तो थिंक टैंक, सेमिनार और प्रायोजित भाषणों में भी बढ़ती ही जा रहीं हैं। अनेक बार जो कुछ गांव-कस्बे की चौपाल पर चर्चित होता है वह बड़े-बड़े विद्वानों की चर्चा और विश्लेषण से अधिक सारगर्भित हो जाता है। यह अलग तथ्य है कि वहां वैसे विशिष्ट मेहमान नहीं होते जिनके दर्शन हमें टीवी पर लगभग प्रतिदिन हो ही जाते हैं। एक दिन उत्तर प्रदेश के एक गांव में स्थानीय लोगों के साथ बैठकर एक चैनल पर हो रही एक परिचर्चा सुनने का अवसर मिला। उस दिन की वह चर्चा काफी हद तक शालीन थी। शोर कम था, मगर श्रोता लगभग हर बिंदु को न केवल समझ रहे थे, बल्कि उस पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे थे। राजनीति, पक्ष, विपक्ष, सत्ता और विरोध, संसद, काला धन, 15 लाख, आलोचना, चाटुकारिता जैसे शब्द अत्यंत विश्वास के साथ उपयोग में आ रहे थे। इस पर कई लोगों ने कहा कि 15 लाख रुपये हर एक के बैंक खाते में सीधे-सीधे जमा करने की बात तो मोदी जी ने कभी नहीं कही। वह तो अपने भाषणों में समझाते थे कि वे विदेशों में जमा कालाधन वापस लाने का हरसंभव प्रयास करेंगे और जितना काला धन विदेश में बताया जा रहा है वह सब आ जाए तो 15-15 लाख सबके हिस्से में आ सकते हैं। यह भी कहा गया कि यह तो हर समझदार जानता है कि 'सरकारी पैसा' तो सरकार ही खर्च करेगी। वह उसे हर एक के खाते में नहीं डाल सकती। इसके विरोध में सुनाई पड़ा 'तो क्या विपक्ष झूठ बोल रहा है?' उत्तर था-'अगर वे सही होते तो यह वायदा क्यों नहीं करते कि वे सत्ता में आने पर सबको 15-15 लाख रुपये देने को तैयार हैं? यह भी तो बताएं कि कहां से और कैसे लाएंगे? बात फिर पचास महीने और पचास साल पर पहुंच गई। ऐसा लगा कि यहां की बहसों पर भी टीवी डिबेट्स का असर पड़ चुका है?

पक्ष-विपक्ष की राजनीति में इस समय परिपक्वता की जो भारी कमी दिखाई दे रही है वह किसी न किसी रूप में हर स्तर पर लोगों का ध्यान खींच रही है, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने गांव के लोगों में समस्या की गंभीरता की समझ देखी। हालांकि ग्रामीण इलाकों में अभी जातिगत लगाव समाप्त नहीं हुआ है। हर बहस उसी आधार पर अपने-अपने नेता के इर्द-गिर्द पहुंच ही जाती है। सभी मानते हैं कि उज्ज्वला, फसल बीमा, जनधन खाते, स्वच्छ भारत और ऐसी ही अन्य योजनाओं में उन्हें भ्रष्ट अधिकारियों को पैसे तो देने पड़े, नोटबंदी के समय तमाम मुश्किलें झेलनी पड़ीं और भ्रष्टाचार से तो पग-पग पर साबका अभी भी हो रहा है। पुलिस, कचहरी, अस्पताल में काम करने वालों के दृष्टिकोण में कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है, मगर इस सबके बाबजूद प्रधानमंत्री के प्रति प्रशंसा भाव दिखता है। जो भारत की राजनीति को न समझता हो उसे यह देखकर घोर आश्चर्य होगा कि कुछ समय पहले तक जातिगत और क्षेत्रीय आधार पर बंटे लोग नरेंद्र मोदी का नाम आते ही कैसे एक स्वर में उनके प्रति समर्थन जताने लगते हैं। यह किसी आश्चर्य से काम नहीं। विश्व में ऐसा अन्य उदाहरण किसी सत्तासीन राजनेता को लेकर दिखाई नहीं देता।

अवधेश राजपूत

आज भारत का जनपक्ष इतना परिपक्व है कि वह राज्य और केंद्र के लिए अलग-अलग राजनीतिक दलों को समर्थन की बात करता है और समझदारी भरे तर्क देता है। यह परिपक्वता दुर्भाग्य से उन राजनीतिक दलों के अधिकांश आकाओं ने प्राप्त नहीं की है। जहां सत्तापक्ष को चुनाव के बाद भारी जिम्मेदारी मिलती है वहीं विपक्ष का काम केवल 'आलोचना और इल्जाम' लगाने तक क्यों और कैसे सीमित हो जाता है? विपक्ष नीतिगत विकल्प क्यों प्रस्तुत नहीं करता हैं। मुझसे पूछा गया, 'भैया, तुम्हें याद है कि इस गांव में तीन बड़े-बड़े बाग थे, चार तालाब थे और अपनी यह नदी कितनी साफ-सुथरी थी, चरागाह थे, लेकिन अब कुछ बचा नहीं है। नदी का पानी जानवर भी नहीं पीते हैं। इसके लिए मोदी तो जिम्मेदार नहीं हैं।'

मैं देख रहा था कि इस पर कोई असहमति व्यक्त नहीं कर रहा था। तालाबों को पुनर्जीवित करने और शौचालय बनाने के लिए शुरू किए गए कार्यों का श्रेय तो मोदी की सोच को ही दिया गया, मगर यह निराशा भी व्यक्त की गई कि काम आधा-अधूरा ही होता है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जब एक बुजुर्ग ने कहा कि 'अब अकेले मोदी भी क्या करें, अफसरों की आदत जो पड़ गई है।' संभवतः यह अभिव्यक्ति भारत के विशाल प्रांगण में फैले अधिकांश व्यक्तियों की है जो 2014 में एक व्यक्ति के राजनीति में उदय पर अपनी सारी आशाएं और अपेक्षाएं उसे सौंपने को तैयार हुए थे। वे अपने उस विश्वास को आगे भी संजोए रखना चाहते हैं। संवेदनात्मक स्तर पर वर्तमान प्रधानमंत्री ने जो स्थान बनाया है वह राजनीति के पंडितों के लिए शोध का विषय बना रहेगा। अधिकांश लोग उन नेताओं से नाराज ही रहते हैं जो प्रधानमंत्री की आलोचना करते समय अनाप-शनाप बोलते हैं।

यह भी उजागर हुआ कि संसद में व्यवहार को लेकर भी लोगों में आक्रोश बढ़ा है। किसानों के संबंध में होने वाली बहस को सभी दलों के चाहने के बाबजूद केवल छह सांसदों ने रुकवा दिया। 'उन्हें अध्यक्ष महोदय ने निकाला क्यों नहीं?' की अभिव्यक्ति अनेक बार सुनी गई। पक्ष-विपक्ष की राजनीति का जो स्वरूप बड़े शहरों और मीडिया में परिलक्षित होता है उससे अलग भी एक बड़ा वर्ग है जो राजनीति में नीति और उसकी आवश्यकता पर दलगत बाध्यता से ऊपर उठकर सोचता है।

जो विचार और तर्क मुझे गांव, खेतों या बचे हुए खलिहानों में मिले वे बड़े-बड़े राजनीतिक पंडितों को भी आश्चर्य में डाल सकते हैं। बानगी-चुनाव घोषणा पत्र अनावश्यक अभ्यास है। इसका कोई महत्व नहीं है। हर चुनाव के छह महीने पहले सत्तारूढ़ दल विस्तृत रूप में देश को बताए कि उसने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों में कितने निभाए और कितने भुलाए? विपक्षी दल भी बताएं कि उन्होंने कितनी जनसेवा की, कैसे-कैसे नीति का पालन करते हुए अनीति का विरोध किया? समय आ गया है कि कानूनन यह प्रावधान हो कि चुनाव से छह महीने पहले हर राजनीतिक दल और यहां तक कि छोटे दल भी एक विस्तृत नीति-पत्र और समयबद्ध क्रियान्वयन योजना तैयार कर देश के सामने प्रस्तुत करें।

(लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं)

response@jagran.com

जनहित को समर्पित सांसद भी थे अटल जी

मोतीलाल वोरा

इतनी बड़ी राजनीतिक हस्ती होने के बाद भी अटल जी निर्वाचन क्षेत्र-लखनऊ की समस्याओं को लेकर हमेशा व्यग्र रहते थे

अटल बिहारी वाजपेयी का जाना एक युग की समाप्ति जैसा है। वह जीवन पर्यंत ऐसे अजातशत्रु रहे जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचते थे। चूंकि वह ग्वालियर के रहने वाले थे इसलिए मेरी अक्सर ही उनसे मुलाकात हो जाती थी। हमारी बातचीत राजनीति ही नहीं, सामाजिक चिंतन पर भी होती थी। उनके नजरिये में कभी दलीय सीमा आड़े नहीं आती थी। जब मैं उत्तर प्रदेश का राज्यपाल था और वह लखनऊ के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता थे तो एक शनिवार लखनऊ पहुंच कर उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, वोरा जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा, जब आपकी इच्छा हो, आइए। इसके बाद मैंने सुझाव दिया कि यदि कल सुबह साढ़े आठ बजे आ जाएं तो हम साथ नाश्ता भी कर लेंगे और बातचीत भी इत्मीनान से हो जाएगी। अगले दिन वह राजभवन आए और कहने लगे, वोरा जी, मेरी यहां कोई नहीं सुनता। सांसद निधि से मैंने काफी पैसा दिया है और उसे कहां कैसे खर्च किया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं देता। मैंने उनसे कहा, आगे से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आप सीधे मेरे संपर्क में रहें। इसके बाद अटलजी ने बताया कि लखनऊ का एक गांव है इंटौजा। वहां की सड़क बहुत खराब है। इस सड़क को बनवाने की मेरी मांग मुख्यमंत्रियों से लेकर अन्य सबने सुनी तो, परंतु आज तक वह सड़क बन नहीं पाई। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन में तो यह सड़क बन ही जाए। इससे मेरे क्षेत्र का एक बड़ा काम हो जाएगा।

बातों ही बातों में उन्होंने यह किस्सा भी सुनाया कि एक नौजवान की नई-नई शादी हुई थी और वह स्कूटर से अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। चूंकि सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे थे इसलिए वह बार-बार मुड़कर पीछे देखता कि कहीं वह गिर तो नहीं गई? एक गड्ढे को पार करते वक्त उसकी पत्नी सचमुच गिर गई। यह किस्सा सुनाकर उन्होंने कहा, वोरा जी इतना बुरा हाल है इंटौजा की सड़क का। मैंने एक हफ्ते के अंदर सड़क निर्माण सामग्री वहां पहुंचाने का आदेश जारी किया और उनसे कहा, अगले सप्ताहांत इस सड़क निर्माण का भूमिपूजन आपके साथ चलकर मैं खुद करूंगा। एक हफ्ते बाद अटलजी लखनऊ आए और हम एक साथ कार में राजनीतिक चर्चा करते हुए वहां पहुंचे तो वाकई सड़क पर एक बड़ा गढ्ढा देख स्कूटर वाले नौजवान का किस्सा याद आ गया। सड़क निर्माण का शुभारंभ करने के दौरान गांव में एक सभा रखी गई। अटलजी ने कहा कि इस गांव में बड़े लंबे समय से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग हो रही है। अगर यह हो जाए तो बड़ी बात होगी। मैंने कहा, यह आपके लिए बहुत छोटा काम है। गांव में इन दोनों का निर्माण अवश्य होगा।

मैंने इसका ऐलान उनकी ही मौजूदगी में किया। गांव में जहां सभा होनी थी वहां भाजपा और कांग्रेस, दोनों दलों के करीब चार हजार लोग मौजूद रहे होंगे। दोनों दलों के स्थानीय नेताओं के भाषण हो रहे थे और वे सब वाजपेयी जी से कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन अभी कुछ समय और रहना चाहिए, क्योंकि राजभवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोगों की बात सुन रहा है।

इसके बाद वाजपेयी जी का भाषण शुरू हुआ और उन्होंने कहा कि मैं वोरा जी को वर्षों से जानता हूं और इस बात से सहमत हूं कि राजभवन में वह अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन मेरी मान्यता है कि राष्ट्रपति शासन की जगह प्रदेश में चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। उनकी यह बात यही जाहिर कर रही थी कि राजनीतिक मूल्यों और लोकतंत्र में उनकी कितनी गहरी आस्था थी।

कार्यक्रम के बाद जब हम एक साथ ही लौट रहे थे तो चिनहट में रुके। वहां उन्होंने कहा, वोरा जी लखनऊ में वाटर वर्क्स बहुत पुराना हो चुका है। लखनऊ की जरूरत को देखते हुए यह अपर्याप्त है। मेरा सुझाव है कि चिनहट में वाटर वर्क्स शुरू किया जाए तो यहां के लोगों की पीने के पानी की कठिनाई दूर हो जाएगी। मैंने कहा, आपका यह काम भी हो जाएगा। मैंने लखनऊ आकर वाटर वर्क्स के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण के खर्च का आकलन कराया तो 98 लाख रुपये की लागत आंकी गई। हमने भूमि अधिग्रहण की राशि जारी कर इसकी प्रक्रिया शुरू करा दी, लेकिन भूमि पूजन से पहले राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया और मैं वापस भोपाल लौट आया। कुछ अर्से बाद जब मैं एक कार्यक्रम में लखनऊ आया तब तक वहां भाजपा सरकार में आ चुकी थी। मैंने संबंधित मंत्री से चिनहट के वाटर वर्क्स का काम पूरा होने के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि इसके लिए पैसा कहां है?

इतनी बड़ी राजनीतिक शख्सियत होने के बाद भी मैंने अटल जी को अपने निर्वाचन क्षेत्र-लखनऊ की समस्याओं को लेकर हमेशा व्यग्र देखा। लखनऊ में जब निशातगंज का पुल बनकर तैयार हो गया तो मैंने अटलजी से अनुरोध किया कि इसका उद्घाटन मैं करूंगा और आप विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। उन्होंने हामी भर दी और उद्घाटन की तारीख भी तय हो गई। इसी बीच नगर निगम चुनावों की घोषणा हो गई। अटलजी ने मुझे फोन किया कि चुनाव की घोषणा होने के बाद पुल का उद्घाटन करना ठीक नहीं होगा। इससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैंने भी उनसे सहमति जताते हुए कार्यक्रम स्थगित कर दिया। यह वाकया जाहिर करता है कि राजनीति में नैतिक मूल्यों को लेकर उनकी निष्ठा कितनी गहरी थी। मुझे याद है कि अटलजी ने तब यह भी कहा था कि पुल तो बहुत आधुनिक बना है, परंतु पुल के नीचे जो दुकानदार हैं उनका भी ख्याल रखना जरूरी है ताकि उनकी रोजी-रोटी में कोई दिक्कत न आए। मैंने वैसा ही किया जैसा अटलजी चाहते थे।

हमारे निजी संबंधों में दलगत राजनीति कभी आड़े नहीं आई। 1998 में चुनाव जीतकर जब मैं लोकसभा पहुंचा तब अटलजी प्रधानमंत्री बन चुके थे और अक्सर संसद में हमारी भेंट हो जाती थी। वह हमेशा बड़े प्रेम से मिलते और हाल-चाल पूछते। प्रधानमंत्री बन जाने के बाद भी निजी रिश्तों की गर्माहट और आत्मीयता को उन्होंने कभी कम नहीं होने दिया।

(लेखक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अभिव्यक्ति

यदि हम जीवन के किसी भी पड़ाव पर पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि कितना कुछ अभिव्यक्त ही नहीं हो पाया। अपने कष्ट, पीड़ा, भावुकता आदि को अभिव्यक्त करने की क्षमता मनुष्य में प्रारंभ से ही पनपती रहती है। अबोध बालक भी किसी न किसी रूप में अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होता है। जैसे बुद्धि की प्रखरता बढ़ती है, मनुष्य सोच समझकर तथा अधिकतर बिना सोचे समझे अपने विचार, अपनी भावनाओं को जब तब अभिव्यक्त करने में लग जाता है। अपने चारों ओर दृष्टि डालें या फिर स्वयं को ही देखें तो यह स्पष्ट होता है कि हम दूसरों के प्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति में तो निपुण होते जा रहे हैं, सच कहिए तो शायद औरों की टीका-टिप्पणी में सभी को एक प्रकार की शांति सी प्राप्त होती है। घर के आंगन से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सभी बस एक दूसरे को नीचा दिखाने की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में लगे दिखते हैं।

'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' तो एक सबसे नवीन व लोकप्रिय नारा बन पड़ा है। अब इस अभिव्यक्ति से कोई आहत होता है तो होए, क्योंकि यह अधिकार उन्हें देश के संविधान ने दिया है। यह मानना उनकी धारणा के विपरीत है कि सभ्य समाज में कल्याणकारी, रचनात्मक, तर्कसाध्य अभिव्यक्ति अपने व दूसरों के जीवन में कितना आनंद प्रदान कर सकती है। कितनी दूरियां पाट सकती है। अभिव्यक्ति ऐसी हो जिसमें गहराई हो, साधना झलके व परंपरा, स्फुरित हो। न कि अपना रोना सुनाओ और दूसरों का सुनो। शांति का संदेश फैलना भी एक प्रकार की सुंदर अभिव्यक्ति है।

इस संघर्ष में यह भी याद रहे कि अपने प्रियजन जिनसे हमें लगाव है, उनके प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति निरंतर करते रहें। उसे केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित न रखें। कहीं ऐसा न हो कि बहुत विलंब हो जाए और मन की बातें अभिव्यक्त ही न हो पाएं। यह हमारा प्रयास सर्वदा रहना चाहिए कि ईश्वर ने जिस अभिव्यक्ति की देन मानव को दी है, उसे सोच समझ कर उपयोग में लाएं। यह प्रवृत्ति समाज व पूरे संसार की बहुत सी समस्याओं का समाधान बन सकती है। यब बात दुर्लभ तो है, लेकिन असंभव नहीं। क्यों न इसका स्वयं से ही शुभारंभ किया जाए।

छाया श्रीवास्तव

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

अटल जी का अनुसरण करने की जरूरत

राजनीति में वैचारिक बदलाव के जनक शीर्षक से लिखे अपने लेख में ए. सूर्यप्रकाश ने अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व के अलग आयाम पर विचार रखा है। अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों के तो उनके विरोधी भी कायल थे। अटल जी अपने विरोधी दल की सरकार की अच्छी नीतियों की प्रशंसा भी करते थे। संसद में मई 1996 में अपने संबोधन में उन्होंने कहा था, 'सत्ता का तो खेल चलेगा। सरकारें आएंगी-जाएंगी, पार्टियां बनेंगी-बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।' लेकिन अफसोस आज देश के लगभग सभी राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक की चिंता ज्यादा और लोकतंत्र की कम है। अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी का मान बढ़ाने के लिए 1977 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में जो भाषण दिया था, वह काफी लोकप्रिय हुआ था। यह पहला मौका था जब संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर हिंदी में किसी ने भाषण दिया था। देश के मौजूदा नेताओं को अटल जी के विचारों पर अमल करना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

स्वर्णिम चतुर्भुज योजना

अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी दूरदृष्टि व अटल इरादों के साथ 1996 में प्रधानमंत्री बनने पर पूरे देश को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की। इन्हें तय समयसीमा में तैयार किया गया और गुणवत्ता व सुरक्षा के लिहाज से बेहतर अंतरराष्ट्रीय स्तर की बनाई गई हैं। इसका देश की जनता को लाभ मिल रहा है।

सौरभ त्यागी, बुराड़ी, दिल्ली

जल वितरण और प्रबंधन

दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को प्रति माह बीस हजार लीटर मुफ्त पानी देने की योजना पर दिल्ली हाईकोर्ट की बार -बार फटकार से केजरीवाल सरकार की आंखें खुलनी चाहिए। पेयजल की बर्बादी को रोकने तथा उचित दर पर स्वच्छ पेयजल देने का प्रयास होता तो सरकार का सराहनीय कदम माना जाता। दिल्ली के नागरिक उचित दर पर स्वच्छ पेयजल की सुविधा चाहते हैं। पेयजल की चोरी और बर्बादी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पानी के बिलों का भुगतान न करने वालों पर जुर्माना लगाकर वसूल की गई राशि को जनहित में लगाना चाहिए। किसी भी सरकार द्वारा मुफ्त वितरण योजना एक नई बीमारी को जन्म देती है। इससे सर्वहित में बचना बहुत जरूरी है।

महेंद्र मान, अलीपुर, दिल्ली

कैसा विकास?

विकास के नाम पर झीलों को खत्म करना कितना खतरनाक है, यह केरल में आई बाढ़ ने बता दिया है। आज बारिश का पानी बाहर नहीं जा पा रहा है और शहरी इलाकों में तांडव मचा रहा है। बड़ी- बड़ी इमारतें बनाने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए। उम्मीद है, भवन निर्माण में जुटी एजेंसियां इससे सबक लेंगी।

मोहम्मद आसिफ, जामिया नगर, दिल्ली

शर्मनाक कृत्य

राजनीति और क्रिकेट दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन गोली व बोली साथ-साथ नहीं चल सकती। कई बार हमारे द्वारा आपसी सौहार्द व बड़ा दिल दिखाने के बावजूद पाक ने दगा किया है। इन सब आघातों को दरकिनार कर व राष्ट्रीय शोक को ठेंगा दिखा पंजाब सरकार के कांग्रेसी मंत्री का पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में जाना व पाक सेना प्रमुख को गले लगाना शर्मनाक कृत्य है।

दीपक गौतम, सोनीपत

युवा पीढ़ी भूल रही मातृभाषा

किसी भी भाषा के साथ उसकी संस्कृति भी जुड़ी होती है। अपने देश के अंदर अगर विभिन्न प्रकार की संस्कृति मौजूद हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण भाषाएं ही हैं जो उन्हें जोड़ने का काम करती हैं। लेकिन देश में तकरीबन 191 भाषाएं ऐसी हैं, जिन्हें लुप्तप्राय माना जा रहा है। मातृभाषा बोलने और सुनने वाले लोग सिर्फ गांवों तक ही सीमित हो गए हैं। आज के समय में छोटे बच्चों को भी स्कूलों में वही भाषाएं सिखाई जाती हैं जिनसे उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त में मदद मिल सके। संस्कृत और उर्दू जैसी भाषाएं तो बस बच्चों को औपचारिकता पूरी करने के लिए पढ़ाई जाती हैं। अक्सर यह बात सुनी जाती है कि हमारा देश तेजी से पश्चिमी परंपराओं को अपनाता जा रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण भाषा ही है, क्योंकि मौजूदा समय में हर व्यक्ति का मानना है कि अंग्रेजी के बिना उनका जीवन अधूरा सा है जो कुछ हद तक सही भी है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा अंग्रेजी है। हमारे देश में भाषाएं रुतबा और ज्ञान का मापदंड बन गई हैं जिसकी वजह से लोग मातृभाषा तो दूर राष्ट्रीय भाषा हिंदी भी बोलने में हिचकते हैं। इस बार मॉरीशस में विश्व हिंदी सम्मेलन में सबसे ज्यादा जोर अलग-अलग देशों से विलुप्त होती हिंदी भाषा को बचाने पर ही दिया गया, यह अच्छी बात है। देश की युवा पीढ़ी अपनी मातृभाषा को भूलते जा रही है तो उसका जिम्मेदार उनके माता -पिता और समाज ही है। जिन्होंने उन्हें उनकी मातृभाषा से पहचान नहीं कराया। अगर देश के लोग चाहते हैं कि हम अपने देश की पुरानी संस्कृति को बचा कर रखें तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी मातृभाषा को विलुप्त होने से बचाने की कोशिश करें।

पीयूष कुमार, नई दिल्ली

ट्वीट-ट्वीट

एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर ढेरों शुभकामनाएं विनेश फोगाट। आपने इतिहास रच दिया, एशियाड में भारत का महिला कुश्ती वर्ग में पहला गोल्ड। पूरे देश को आप पर गर्व है।
योगेश्वर दत्त@DuttYogi

दूध के मामले में अधिशेष स्थिति वाले राज्य पंजाब में बीते दस दिनों में लिए गए दूध के 60 प्रतिशत से अधिक नमूनों में मिलावट पाई गई है। क्या इस पर सरकारी मशीनरी को सक्रियता से कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अफसोस कि मीडिया तो छोड़िए सोशल मीडिया में भी इसे लेकर आक्रोश नहीं दिखता।
देविंदर शर्मा @Devinder_Sharma

मॉरीशस में चल रहे विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों से आए हुए हिंदी प्रेमी विदेशी लोगों ने हिंदी भाषा में मुझसे पूछा-भारत में लोग अंग्रेजी को इतनी तवज्जो क्यों देते हैं जबकि हिंदी एक बहुत ही खूबसूरत भाषा है?
किरण रिजिजू@KirenRijiju

पाकिस्तानी सेना ने न केवल अपनी नई कठपुतली इमरान 'तालिबान' खान को चुनाव जितवाकर प्रधानमंत्री बना दिया, बल्कि उनकी कैबिनेट में अपने पसंदीदा चेहरों को भी जगह दिला दी। खान के मंत्रिमंडल में अधिकांश चेहरे जनरल मुशर्रफ के सैन्य शासन में भी काम कर चुके हैं।
ब्रह्मा चेलानी@Chellaney

जनपथ

गाली देने के लिए चहिए था इक वीर,
इसीलिए फिर खुल गई अय्यर की तकदीर।
अय्यर की तकदीर झरें जिह्वा से कंकर,
बड़के तीरंदाज बनेंगे फिर मणिशंकर।
राहुल जी दिलखोल बजाएंगे अब ताली,
जब-जब अय्यर साब बकेंगे भद्दी गाली।

-ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 29 अंक 35